



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1981/फाल्गुन 4, 1902

No. 80]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1981/PHALGUNA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1981

का.आ. 125(अ)/15ए/आई डी आर ए/81.—यतः मं. कुमार-धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कुमारधुबी, जिला धनबाद के नाम से जानी जाने वाली कम्पनी के कुछ ऋणदाताओं द्वारा दिये गये आवेदनों के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 15 दिसम्बर, 1980 को कम्पनी को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किया तथा कम्पनी का कारोबार नहीं चल रहा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि आम जनता के हितों, और विशेषकर उक्त कम्पनी के स्वामित्व वाले इस औद्योगिक उपक्रम (कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड) (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा जायेगा) में उत्पादन किये जाने वाली वस्तुओं के हितों में इस औद्योगिक उपक्रम को चलाने अथवा पुनः चालू करने की संभावनाओं की जांच पड़ताल की जाये ;

और यतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी संभावना की जांच पड़ताल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिये गये आवेदन पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जनवरी, 1981 के एक आदेश द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है ;

अब, अतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः चालू करने की संभावना की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है :—

1. श्री एन. राजन, अध्यक्ष  
वित्तीय सलाहकार और अपर सचिव,  
उद्योग मंत्रालय,  
नई दिल्ली ।
2. श्री हरि भूषण, सदस्य  
सलाहकार (तकनीकी),  
उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग,  
नई दिल्ली ।
3. श्री एस. कन्नन, सदस्य  
उप सचिव,  
उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग,  
नई दिल्ली ।

इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि में उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

[फा. ए. 2(4)/81-सी. यू. एम्.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1981

**S.O. 125(E)/15A/IDRA/81.**—Whereas on the basis of applications made by some creditors of the company known as Messrs Kumardhubi Engineering Works Limited, Kumardhubi, District Dhanbad, the High Court of Calcutta passed orders on the 15th December, 1980 for winding up the company and the business of the company is not being continued ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is necessary in the interests of the general public, and in particular, in the interest of production of the articles manufactured in the industrial undertaking (known as Kumardhubi Engineering Works Limited) owned by the said company (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) to investigate into the possibility of running or re-starting the said industrial undertaking ;

And, whereas, on an application made by the Central Government under section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the High Court of Calcutta praying for permission to make an investigation into such possibility, the High Court of Calcutta has, by an

order dated 22nd January, 1981, granted the requisite permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making an investigation into the possibility of re-starting the said industrial undertaking, a body of persons consisting of —

1. Shri N. Rajan, — Chairman  
Financial Adviser & Additional Secretary,  
Ministry of Industry,  
New Delhi,
2. Shri Hari Bhushan, —Member  
Adviser (Technical),  
Ministry of Industry,  
Department of Heavy Industry,  
New Delhi.
3. Shri S. Kannan, — Member  
Deputy Secretary,  
Ministry of Industry,  
Department of Heavy Industry,  
New Delhi.

The above body shall submit its report within a period of one month from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 2(4)/81-CUS]

R. N. CHOPRA, Additional Secy.